



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, 29 अगस्त 2014/भाद्र 7, 1936

No. 219]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2014/BHADRA 7, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2014

**विषय :** चीन जन.गण. के मूल की या वहां से निर्यातित ग्लिकलेजाइड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की जांच।

सं. 14/5/2014-डीजीएडी.—मै. बाल फार्मा लि., बंगलौर (जिसे आगे याचिकाकर्ता/आवेदक भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लिकलेजाइड के आयातों पर पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा यथासंशोधित सीमाशुल्क (पहचान, आकलन और पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क के संग्रहण तथा धति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुरूप निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

### घरेलू उद्योग और उसका आधार

2. यह आवेदन विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में मै. बाल फार्मा लि. द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वे भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र विनिर्माता है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है

कि कुछ अन्य उत्पादकों जो संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण में लगे हुए थे, ने पिछले कुछ वर्षों से अपना विनिर्माण बंद कर दिया है। इस याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया है कि इस याचिकाकर्ता अथवा इससे संबंधित किसी पक्ष द्वारा संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पादन के कुल उत्पाद में “एक बहुत बड़ा अनुपात” है, अतः याचिकाकर्ता इस आधार को संतुष्ट करता है तथा वह इस नियमावली के आशय के भीतर घरेलू उद्योग है।

### **विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जांच के प्रयोजन से विचाराधीन उत्पाद “ग्लिक्लेजाइड” है। ग्लिक्लेजाइड एक औषधि है जिसका रासायनिक नाम “1-[हेक्साहाइड्रोसाइक्लोपेंटा (सी) पायरल-2 (1एच)-वाईएल]-3- (4-मेथिलफिनायल) सल्फोनिल) यूरिया” है और इसमें 99.0 प्रतिशत से कम तथा 101.0 प्रतिशत अधिक C15H21N3O3 होता है जिसकी गणना शुष्क पदार्थ के संदर्भ में की जाती है। ग्लिक्लेजाइड देखने में श्वेत अथवा श्वेत जैसा पाउडर, व्यवहारिक रूप से जल में न घुलने योग्य, डिक्लोरोमिथेन में आसानी से घुलने योग्य, एसीटोन में बमुश्किल घुलने योग्य तथा इथीनोल में बहुत कम घुलने योग्य (96 प्रतिशत) होता है।

4. ग्लिक्लेजाइड एक व्यापक औषधि है जिसका उपयोग एंटीडायबिटिक/हाइपोग्लीसेमिक औषधियों से संबंधित फार्मास्युटिकल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ग्लिक्लेजाइड का उपयोग स्थिर, धीमा, गैर केटोसिस प्रोन, टाइप-2 डायबिटीज के ग्लिक्लेजाइड कारगर डायबिटीज में हाइपर ग्लीसिनिया के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब डायबिटीज पर उचित खान-पान प्रबंधन और व्यायाम द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता है अथवा जब इंसुलिन थेरेपी उपयुक्त नहीं होती।

5. संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण शुल्क मद 2942 00 90 के अंतर्गत सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय-29 के अंतर्गत किया जा सकता है। इस याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का आयात अन्य उप-शीर्ष जैसे 2911 00 90, 2912 19 90, 2921 59 90, 2924 19 00, 2927 00 90, 2930 90 99, 2932 99 00, 2933 19 90, 2933 59 90, 2933 99 00, 2934 99 00, 2935 00 90, 2937 19 00, 2941 90 11, 2941 90 90, 2942 00 11, 2942 00 90, 3822 00 11, 3822 00 19, के अंतर्गत भी किया जा रहा है। एच एस कोड केवल संकेतात्मक है और उत्पादन विवरण हर परिस्थिति में विद्यमान रहेगा।

### **समान वस्तु**

6. इस आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तुएं उस देश से भारत में पारित किए जा रहे संबद्ध सामानों के अनुरूप हैं। इस आवेदक ने दावा किया है कि इस याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयातित ग्लिक्लेजाइड में इन सामानों का भौतिक एवं रासायनिक लक्षण, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण जैसे मानदंडों के मामले में तुलनीय लक्षण होते हैं। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें इस नियमावली के अंतर्गत “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन से भारत में इस आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देश से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों का “समान वस्तु” के रूप में माना जा रहा है।

## शामिल देश

7. वर्तमान याचिका चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

## सामान्य मूल्य

8. इस याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और इसमें इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुरूप सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के संबंध में यह पूर्वानुमान किया जाता है कि चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में काम कर रहे हैं। गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान को देखते हुए तथा प्रतिवादी निर्यातिकों द्वारा उसका खंडन किए जाने पर चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य का आकलन इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के संदर्भ में किया गया है। इस आवेदक ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चे तथा उचित लाभ का विधिवत समायोजन करने के पश्चात भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

## निर्यात कीमत

9. इस आवेदक ने डीजीसीआई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। कमीशन, जलमार्ग भाड़ा, पत्तन प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, वैट अंतर और बैंक कमीशन के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है।

## पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना एक्स फैक्ट्री स्तर पर की गई है जो संबद्ध देश के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन दर्शाता है। प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध सामानों का समान मूल्य एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जो प्रथमदृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध सामानों का पाटन संबद्ध देश से निर्यातिकों द्वारा भारतीय बाजार में किया जा रहा है। पाटनरोधी जांच शुरू करने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त पाटन मार्जिन का व्यापक साक्ष्य है।

## क्षति तथा कारणात्मक संबंध

11. इस आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से बहुत अधिक क्षति हुई है। विचाराधीन उत्पाद की मांग, क्षति अवधि में बढ़ी है। संबद्ध आयात कुल मिलाकर बढ़े हैं। इन आयातों से क्षति की अवधि में घरेलू कीमतें कम हुई हैं। घरेलू उद्योग पर आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन, लाभ, नियोजित पूँजी पर आय तथा नकद लाभ जैसे मानदंडों के संबंध खराब हुए हैं। घरेलू उद्योग को बहुत अधिक वित्तीय घाटा, नकद घाटा तथा निवेश पर ऋणात्मक लाभ हो रहा है। पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य सिद्ध करने हेतु संबद्ध देश से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं।

12. और जबकि प्राधिकारी ने प्रथमदृष्टया पाया है कि संबद्ध देश से शुरू की गई या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन; घरेलू उद्योग को क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच आकस्मिक संपर्क के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। प्राधिकारी एतद्वारा कथित पाटन के संबंध में तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में नियमावली के नियम 5 के संदर्भ में जांच प्रारंभ करती है।

तथा कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव को निर्धारित करने के लिए तथा यदि पाटनरोधी शुल्क कोई हो, तो उसकी मात्रा की सिफारिश करने के लिए घरेलू उद्योग को हर्दृ क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### **जांच अवधि (पी ओ आई)**

13. याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि (पीओआई) का प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2013 से 30 मार्च, 2014 तक के लिए किया है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजन से, पिछले 3 वर्षों अर्थात् अप्रैल 10 से मार्च, 11 अप्रैल, 11 से मार्च, 12, अप्रैल 12 से मार्च, 13 के आंकड़ों तथा जांच की प्रस्तावित अवधि पर विचार किया गया है।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

14. संबद्ध देश में निर्यातिक, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, इससे संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने तथा निर्धारित प्रपत्र में तथा तरीके से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:—

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,**  
**5, संसद मार्ग,**  
**नई दिल्ली-110001**

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय सूचना देने वाले किसी पक्षकार से अपेक्षित है कि वह अन्य पक्षकारों को उसकी एक अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराए।

### **समय सीमा**

16. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजा जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हॉर्ड कॉफी और सॉफ्ट कॉफी में प्रस्तुत की जाए।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तब प्रश्नावली के उत्तर सहित इस प्राधिकारी के समक्ष सूचना प्रस्तुत करने वाले (संबद्ध परिशिष्ट/अनुबंध सहित) पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे दो अलग-अलग सैट में सूचना दायर करें:—

- (क) एक सैट जो गोपनीय के रूप में अंकित हो (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमिका आदि सहित) तथा
- (ख) दूसरा सैट जो अगोपनीय के रूप में अंकित हो (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमिका आदि सहित)
19. प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप में “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” सूचना स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। ऐसे किसी अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक पाठ की पांच सैटों में हार्ड प्रतियों सहित प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होगी।
20. गोपनीय पाठ में वे सभी सूचनाएं होंगी जो प्रकृति से गोपनीय हैं और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसे इस सूचना के प्रदाता गोपनीय होने का दावा करते हैं। गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना अथवा वे सूचना जिनके गोपनीय होने का दावा अन्य कारणों से किया गया हो, के लिए, सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
21. वह सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया हो, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना संभव नहीं हो) /सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ अगोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश काफी विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तब प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
23. सार्वजनिक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं लेंगे।
24. संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### असहयोग

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दाढ़ू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2014

**Subject:** Anti Dumping investigation concerning imports of Gliclazide, originating in or exported from China PR.

**F.No.14/5/2014-DGAD.**—M/s. Bal Pharma Ltd., Bangalore (hereinafter also referred to as the Petitioner or applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on the imports of Gliclazide, originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

**Domestic Industry and Standing**

2. The Application has been filed by M/s. Bal Pharma Ltd., as domestic industry of the product under consideration. According to the Petitioner, they are the sole manufacturer of the subject goods in India. It has been claimed by the petitioner that some other producers who were engaged in the manufacturing of subject goods seem to have discontinued their manufacturing since last few years. The petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party from the subject countries. Since the production of the petitioner accounts for “a major proportion” in the total production of the product under consideration in India, the petitioner satisfies the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rules.

**Product under consideration**

3. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Gliclazide”. It is a drug with a chemical name of “1-(Hexahydrocyclopenta (c) pyrrol-2 (1H)-yl)-3-{(4-methylphenyl) sulfonyl} urea” and contains not less than 99.0% and not more than 101.0% of C<sub>15</sub>H<sub>21</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>, calculated with reference to the dried substance. Gliclazide is a white or almost white powder in appearance practically insoluble in water, freely soluble in dichloromethane, sparingly soluble in acetone and slightly soluble in ethanol (96%).

4. Gliclazide is a Bulk Drug used in pharmaceutical preparations concerning Anti diabetic/Hypoglycemic drugs. Gliclazide is used for control of hyperglycemia in gliclazide-responsive diabetes mellitus of stable, mild, non-ketosis prone, type 2 diabetes. It is used when diabetes cannot be controlled by proper dietary management and exercise or when insulin therapy is not appropriate.

5. The subject goods are classifiable under Chapter 29 of the Custom Tariff Act, 1975 under Tariff item 2942 00 90. As per the petitioner's claim subject goods are also being imported under other sub-headings such as 2911 00 90, 2912 19 90, 2921 59 90, 2924 19 00, 2927 00 90, 2930 90 99, 2932 99 00, 2933 19 90, 2933 59 90, 2933 99 00, 2934 99 00, 2935 00 90, 2937 19 00, 2941 90 11, 2941 90 90, 2942 00 11, 2942 00 90, 3822 00 11, 3822 00 19. The HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

**Like Article**

6. The applicant has claimed that the subject goods being produced by the domestic industry are identical to the subject goods being dumped into India from subject country. The applicant has claimed that Gliclazide produced by the petitioner and imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology,

functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

### **Countries involved**

7. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR.

### **Normal Value**

8. The petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules. The applicant has determined the normal value based on cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

### **Export Price**

9. The applicant has determined the export price on the basis of data published by the DGCI&S. Price adjustments have been claimed on account of commission, ocean freight, port expenses, inland freight, marine insurance, VAT difference and bank commission.

### **Dumping Margin**

10. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

### **Injury and Causal Link**

11. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports. The demand for the product under consideration has increased over the injury period and subject imports have increased in absolute terms. The imports are undercutting the domestic prices. The imports have suppressed/depressed the domestic prices over the injury period. With regard to consequent impact of the imports on the domestic industry, it is noted that performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as profits; return on capital employed and cash profits. The domestic industry is suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investments. There is sufficient *prima facie* evidence of injury to the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

12. And whereas, the Authority *prima facie* finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

### **Period of Investigation (POI)**

13. The period of investigation (POI) is from 1st April, 2013 to 31st March, 2014. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. Apr'10-Mar'11, Apr'11-Mar'12, Apr'12-Mar'13 and the period of investigation has been considered

**Submission of Information**

14. The exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority**  
**Directorate General of Anti-Dumping And Allied Duties**  
**Department of Commerce,**  
**Jeevan Tara Building, 4th Floor,**  
**5, Parliament Street,**  
**New Delhi -110001**

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**Time Limit**

16. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

**Submission of information on confidential basis**

18. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:—

- (a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- (b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

19. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

20. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

24. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of Public File**

25. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

#### **Non-cooperation**

26. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J K DADOO, Designated Authority